भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 806
सोमवार, 28 जुलाई, 2025 (6 श्रावण, 1947, (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

वाणिज्यिक विमानपत्तनों का निर्माण

806. श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वाणिज्यिक विमानपत्तन के रूप में निर्मित विमानपत्तनों की संख्या कितनी है;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार अगले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक विमानपत्तनों के रूप में किन-किन विमानपत्तनों के निर्माण पर विचार कर रही है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): आज की तारीख में, देश में 162 हवाईअड्डे प्रचालनशील हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, चार (4) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे अर्थात् अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर (होलोंगी), गोवा में मोपा, कर्नाटक में शिवमोग्गा और गुजरात में राजकोट (हीरासर) का निर्माण और उन्हें प्रचालनशील किया गया है।

(ग) और (घ): भारत सरकार (जीओआई) ने देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, भारत सरकार ने देश भर में 24 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों नामतः ओडिशा में पुरी, तमिलनाडु में पारंदूर, राजस्थान में कोटा, गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलबुरगि, विजयपुरा, हसन और शिवमोग्गा, मध्य प्रदेश में डबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और राजकोट (हीरासर), पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगदरथी, भोगापुरम और ओरवाकल (कुर्नूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है।

इनमें से, 12 ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे नामतः दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कलबुरगि, ओर्वाकल (कुर्नूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोग्गा और राजकोट (हीरासर) प्रचालनरत हो गए हैं। जीएफए नीति, 2008 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण, आर एंड आर आदि सहित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की होती है। हवाईअड्डा परियोजनाओं के पूरा होने की

समयसीमा कई कारकों जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरियां उपलब्ध होना, वित्तीय समापन, आदि पर निर्भर करती है।

******